साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 23-29 सितंबर 2024 वर्ष-10, अंक-23
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-जल संरक्षण पर साझा किए विचार, पौधरोपण पर जोर दिया, -डिंडोरी के गांव में चलाई थी जल संकट से निपटने की मुहिम

राष्ट्रपति के सामने डिंडोरी की उजियारो बाई ने सुनाई अपने संघर्ष की कहानी और मंच से ही दिया जल संरक्षण का मंत्र

जागत गांव हमार, भोपाल।

देश की राजधानी दिल्ली के मंडपम भवन में आयोजित आठवें भारत जल सप्ताह के आयोजन में मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले की आदिवासी महिला उजियारो बाई ने अपने विचार साझा किए। भारत जल सप्ताह के दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के समक्ष जिले के ग्राम पोंडी निवासी उजियारो बाई ने गांव में जल संरक्षण, बचाव और इसके उपयोग पर अपने संघर्ष से सफलता तक की कहानी सुनाया। उजियारो बाई ने बताया कि पोंडी ग्राम में लगातार पेड़ काटे जाने और पथरीली जमीन होने के कारण वर्षा का जल संग्रहित नहीं हो पाता था। लोगों को पीने के पानी के लिए झरनों व दूषित पानी के स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। जिससे जलजनित बीमारियों के फैलने से प्रति वर्ष दर्जनों लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने पानी की इस समस्या को देखते हुए मुहिम चलाई और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी। उजियारों बाई ने गांव में कई बार चौपाल लगाया व लोगों को घर-घर जाकर जल, जंगल बचाने और वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए प्रेरित किया। छोटे-छोटे जरूरी नियम बनाए गए। पेड़ों की कटाई रोकी गई और पौधरोपण किया गया।

पेड़ बचाने का दिया संदेश

उजियारो बाई ने बताया कि इस कड़ी मेहनत और लगनशील प्रयास से अब पोंड़ी ग्राम के पुराने झरने रिचार्ज हो गए हैं। गांव के जल स्त्रोतों में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप अब गांव के लोगों को हर घर में शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि पेड़ है तो पानी है, पानी है तो जिंदगानी है। उजियारो बाई के प्रयास आज अध्ययन और शोध का विषय है, जिसे दक्षिण आफ्रीका जैसे देशों के द्वारा समझा और अपनाया जा रहा है।

मप्र का नाम किया रोशन

कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि उजियारो बाई ने न केवल जल संरक्षण अपितु कृषि क्षेत्र में उन्नत कार्य कर डिंडोरी जिले का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। भारत जल सप्ताह की अवधारणा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामने लाई गई, जिसका उद्देश्य पारंपरिक तरीकों से परे अत्याधुनिक समाधानों को बढ़ावा देकर बढ़ते जलसंकट, प्रदूषण और मौजूदा जल आपूर्ति के अकुशल उपयोग के मुद्दों को सामने लाना है। इसका लक्ष्य जन जागरूकता पैदा करना, उपलब्ध जल के संरक्षण, बचाव और उसके उत्कृष्ट उपयोग के लिए प्रमुख रणनीतियों को लागू करने के लिए समर्थन प्राप्त करना है। पहली बार भारतीय जल सप्ताह का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था।

कर्मचारी संवाद में सीएम बोले, हर किसान परिवार को मिले 50 हजार रुपए बोनस

10 लाख टन तक पहुंचाया जाएगा उज्जैन दुग्ध संघ का उत्पादन

मप्र में दुग्ध संघ की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी सरकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। शासन का प्रयास है कि दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसान अधिकाधिक रूप से लाभान्वित हों। प्रत्येक किसान परिवार के पास कम से कम 50 हजार रुपए बोनस राशि पहुंचे। उज्जैन दुग्ध संघ की उत्पादन क्षमता को 10 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघ की भूमिका को धरातल स्तर तक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कृषि आधारित मध्यप्रदेश में किसानों की आय में और अधिक वृद्धि हो इसके लिए शासन कृत-संकल्पित है। प्रदेश की कृषि विकास दर को और आगे ले जाना है। इसमें पशुपालक दुग्ध उत्पादक किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा मप्र

शासन का प्रयास है कि दुग्ध उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो। इसमें दुग्ध सहकारिता की बड़ी भूमिका रहेगी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ी हुई मात्रा की खपत के लिये भी कार्य किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दुग्ध खपत के लिये दुग्ध संघ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध सहकारी संघ को मजबूत बनाने के साथ किसानों के लिए जितनी भी राशि चाहिए वह दी जाएगी। धरातल स्तर तक दुग्ध सहकारी संघ की भूमिका को प्रभावी बनाया जायेगा।

प्राफिट 100 करोड़ करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ मेरा अपना परिवार है। वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ की ढाई लाख टन की क्षमता में वृद्धि कर 10 लाख टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके प्रॉफिट को भी बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक ले जाना है। साथ ही कर्मचारी हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि, दुग्ध संघ से जुड़े पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बंगाल अव्वलः छह राज्यों में 75 फीसदी उत्पादन

शिमला मिर्च की पैदावार में छठें स्थान पर मध्य प्रदेश

जागत गांव हमार, भोपाल।

शिमला मिर्च का नाम सुनते ही दिमाग में तीखे और चटपटे स्वाद की याद आती है। शिमला मिर्च के उत्पादन में मध्यप्रदेश छठवे नंबर है। भारत में सबसे अधिक शिमला मिर्च का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यहां के किसान हर साल शिमला मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। देश के कुल शिमला मिर्च उत्पादन में बंगाल की 29.61 फीसदी की हिस्सेदारी है। यहां की मिट्टी और जलवायु शिमला मिर्च की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। देश में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों में शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं उत्पादन की बात करें तो इसमें कर्नाटक का भी नाम है, जहां के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। देश के कुल शिमला मिर्च उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 10.54 फीसदी है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल सब्जी और अन्य चाईनीज व्यंजन में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। वहीं, उत्पादन के मामले में भारत के टॉप तीन राज्यों में तीसरा नंबर हरियाणा का है। यहां शिमला मिर्च का 10.49 फीसदी उत्पादन होता है। बाजार में तीन रंगों की शिमला मिर्च मिलती है, जिसमें हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च शामिल है।

चौथे नंबर पर झारखंड

अब जान लीजिए कि झारखंड शिमला मिर्च के उत्पादन में चौथे नंबर पर है। इस राज्य के किसान हर साल 10.10 फीसदी शिमला मिर्च का उत्पादन करते हैं। वहीं उत्पादन के मामले में पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। यहां शिमला मिर्च का 8.68 फीसदी उत्पादन होता है।

मप्र में 6.16 फीसदी उत्पादन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के (वर्ष 2023-24) आंकड़ों के अनुसार शिमला मिर्च की पैदावार में छठे स्थान पर मध्य प्रदेश है। यहां हर साल किसान 6.16 फीसदी शिमला मिर्च का उत्पादन करते हैं। वहीं ये छह राज्य मिलकर 75 फीसदी शिमला मिर्च का उत्पादन करते हैं। शिमला मिर्च की खेती करके किसान बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बाजारों में पूरे साल रहती है।

अन्नदाताओं की आय के साथ बढ़ेगी उपज, कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा

किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने जारी रहेगी पीएम आशा योजना, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

जागत गांव हमार, भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं में मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने को मंजूरी दे दी। इस विस्तार से 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ का वित्तीय खर्च आएगा। इस फैसले पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम-आशा के अंतर्गत एकीकृत किया है। इस एकीकरण का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्यों को स्थिर करना है, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं के लिए आसानी से खरीदे जाने योग्य बनाया जा सके। सरकार की मानें तो पीएम-आशा की एकीकृत योजना को संचालित करना ज्यादा प्रभावशील होगा जो पहले कभी नहीं था। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

100 फीसदी होगी तुअर उड़द की खरीद

पीएम-आशा में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष के तत्व भी शामिल होंगे। साथ ही इसमें मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को भी जगह मिली है। मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर नोटिफाइड दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद 2024-25 से इन नोटिफाइड फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन के 25 फीसदी पर होगी। इससे राज्यों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए किसानों से एमएसपी पर इन फसलों की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी। हालांकि साल 2024-25 सीजन के लिए तुअर, उड़द और मसूर के मामले में यह सीमा लागू नहीं होगी। 2024-25 सीजन के दौरान तुअर, उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद होगी जैसा कि पहले तय किया गया था।

बाजार में कीमतें रहें नियंत्रित

मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के विस्तार से दालों और प्याज का रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखने, जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने में मदद मिलेगी और वह भी सस्ती कीमतों पर। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से ऊपर होंगी, तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व-पंजीकृत किसानों सहित बाजार मूल्य पर दालों की खरीद की जाएगी। बफर रखरखाव के अलावा, पीएसएफ योजना के तहत टमाटर जैसी अन्य फसलों और भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री में हस्तक्षेप किया गया है।

तिलहन उत्पादन बढ़ाकर 40 फीसदी

राज्यों को अधिसूचित तिलहनों के लिए एक विकल्प के रूप में मूल्य घाटा भुगतान योजना के कार्यान्वयन के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कवरेज को राज्य तिलहन उत्पादन के मौजूदा 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही कार्यान्वयन अवधि को भी 2018-19 में 25 फीसदी से बढ़ा दिया गया है। किसानों के लाभ के लिए 3 महीने से 4 महीने तक का समय दिया जाएगा। एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच अंतर का मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो एमएसपी के 15 फीसदी तक सीमित है।

सरकार ने बढ़ाई गारंटी

सरकार ने इसे रिन्यू किया है और किसानों से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से किसानों से एमएसपी पर दलहन, तिलहन और खोपरा की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड किसान शामिल हैं। जब कभी भी कीमतें गिरेंगी तो ये संगठन आगे आएंगे। इससे किसानों को खेती करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। देश में इन फसलों की अधिक पैदावार होगी और इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

टमाटर, प्याज-आलू रहें सस्ते

बाजार हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन का विस्तार बदलावों के साथ होगा। जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। सरकार ने कवरेज को उत्पादन के 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है और एमआईएस के तहत भौतिक खरीद के बजाय अंतर भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने का एक नया विकल्प जोड़ा है। इसके अलावा, टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के मामले में, शीर्ष कटाई के समय उत्पादक राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के बीच टीओपी फसलों की कीमत के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने किसानों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए परिवहन और स्टोरेज खर्च को उठाने का निर्णय लिया है। नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगी, बल्कि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए शीर्ष फसलों की कीमतों को भी कम करेंगी।

80-100 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार

किसानों के लिए फायदेमंद गेहूं एचडी-3385

जागत गांव हमार, भोपाल।

खरीफ फसलों का सीजन अब खत्म होने वाला है और रबी फसल का सीजन शुरू होने वाला है। इस सीजन में किसान धान की फसल काटने के बाद गेहूं की रोपाई शुरू कर देंगे। पिछले दो-तीन वर्षों से देखा जा रहा है कि गेंहू की खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। पर पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि खराब मौसम के कारण गेहूं की पैदावार पर असर हो रहा है। इससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक ऐसे मौसम परिवर्तन के दौरान अच्छी पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों को विकसित कर रहे हैं जो रोग प्रतिरोधी भी है। इसी के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने हाल में एक गेहूं की एक नई वेरायटी विकसित की है जिसका नाम एचडी 3385 रखा गया है। गेहूं की यह किस्म अधिक उपज देने वाली किस्म है। अगर समय पर इस गेहूं की बुवाई की जाती है तो गेहूं अनुकूल परिस्थितियों में प्रति हेक्टेयर 80-100 क्विंटल तक की पैदावार देती है। गेहूं की यह किस्म उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के खेतों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं की इस बेहतरीन किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है।

इतनी है प्रति हेक्टेयर पैदावार

इन नई किस्म का प्रसार देश के सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में किया जाएगा। गेहूं की यह किस्म मौसम परिवर्तन रोधी होने के साथ-साथ रतुआ रोधी भी है। इसके अलावा अन्य रोगों के प्रति भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। इस किस्म का औसत उत्पादन लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसकी उपज क्षमता बढ़कर 73.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इस किस्म की अधिकतम उपज क्षमता 80-100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हालांकि जब अलग-अलग स्थानों और जलवायु परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया गया तब इसकी उपज क्षमता 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रही।

नहीं लगता है करनाल बंट रोग

गेहूं की इस किस्म में करनाल बंट नामक रोग नहीं लगता है, साथ ही यह अधिक तापमान को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसके पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर तक होती है। गेहूं की नई किस्म एचडी 3385 में टिलरिंग की समस्या नहीं आती है। इसके साथ ही इसमें येलो, ब्राउन और ब्लैक रस्ट की समस्या नहीं आती है। आईएआरआई करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. शिवकुमार यादव ने बताया कि के इस किस्म की बुवाई पंजाब हरियाणा, हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर में किसान अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी बोवनी कर सकते हैं।

आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर से शुरू होगी, हर मंगलवार करेंगे किसानों से बात

किसानों से हर हफ्ते सीधा संवाद करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज

- सरकार का उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्र का विकास करना
- किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाने पर केंद्र सरकार का पूरा जोर

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्र का विकास करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित किए थे। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए किसानों को समय पर उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है। किसानों तक बीज पहुंचाने के लिए कृषि समेत शैक्षिक संस्थानों को भी लगाया गया है। किसानों की उपज खरीद के लिए एमएसपी दी जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े सवाल पर कहा कि इसके लिए कोशिश जारी है और सर्वे किए जा रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों में कई किसानों की आय डबल से भी ज्यादा हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर से शुरू होगी और वह हर मंगलवार किसानों, किसान संगठनों से सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों में तापमान बढ़े तो भी उत्पादन न घटे, कम पानी अच्छी फसलें करने, कीट-रोग की रोकथाम के लिए नए बीजों किसानों को सौंपी गई है। फसलों में रोग की पहचान के लिए नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसानों को बीज समय पर मिले उसके लिए रणनीति बनाई गई है। इसको लेकर राज्यों से रिपोर्ट मांग ली गई है कि गेहूं का उत्पादन उनके राज्य में कितना होगा। उस हिसाब से किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिल सकें। कृषि और शिक्षा संस्थानों को भी बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसानों तक इनकी पहुंच आसान और तेज की जा सके।

किसानों को सस्ती कीमत पर खाद दी जा रही

यूरिया की एक बोरी 2366 रुपये की आती है, हम किसानों को 266 रुपये में दे रहे हैं। डीएपी 1350 रुपये में सरकार दे रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते उर्वरकों की देरी को पूरा करने के लिए सरकार ने 24475 हजार करोड़ रुपये रबी सीजन के लिए मंजूरी दी गई है। फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती पर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मिशन आएगा, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सखी योजना, ड्रोन दीदी योजना के जरिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो किसानों की मदद कर रही हैं। सरकार की कोशिश है कि आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर ने 100 दिनों में यह काम किया है।

फसलों के लिए 9 सेंटर बनाए जा रहे

कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन की लागत घटाना हमारा उद्देश्य है। बीजों की ऐसी वैराइटी विकसित की गई है जिससे पानी की लागत घट जाएगी। धान की डायरेक्ट सीडेड, बाजरा समेत अन्य फसलों की ऐसी किस्में विकसित की गई हैं, जो किसानों की लागत घटाएंगी। किसानों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 7 करोड़ से ज्यादा किसान लाभ पा चुके हैं। 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान 100 दिनों के अंदर सरकार ने केसीसी के लिए किया है। हमारा लक्ष्य केवल परंपरागत फसलें करने का नहीं है, हम उन्नत फसलों और आधुनिक तकनीकी पर फोकस कर रहे हैं। बागवानी, हार्टीकल्चर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग-अलग फसलों के लिए देश में 9 सेंटर बनाए जा रहे हैं। कृषि विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

- वैज्ञानिक किसान तक जानकारी जल्दी से पहुंचाएं
- किसान कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा

लैब टू लैंड - यानी वैज्ञानिक किसान तक जानकारी जल्दी से पहुंचाएं इसके लिए आधुनिक आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसमें हर महीने आधुनिक रिसर्च, तकनीक की जानकारी वैज्ञानिक किसान को देगें। इस प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए किया जाएगा। आधुनिक कृषि चौपाल के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिसे वह खुद मॉनीटर करेंगे। इसमें किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किसान अपनी समस्याओं का हल जानेंगे और दिक्कतें बता सकेंगे।

किसानों से हर मंगलवार सीधा संवाद होगा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। इसके लिए हर मंगलवार को दोपहर के भोजन से पहले किसानों, किसान संगठनों से संवाद किया जाएगा। ताकि कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। अन्नदाता के जीवन को बेहतर की कोशिश है। खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए हम काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संवाद आने वाले मंगलवार से शुरू होगा। अगर मैं उस दिन उपलब्ध नहीं हुआ तो सोमवार या बुधवार को संवाद किया जाएगा।

सरकार का दावा: एक लाख हेक्टेयर रकबे में आई गिरावट

बाजरा का एमएसपी 125 रुपए बढ़ने के बाद भी किसान खफा

जागत गांव हमार, भोपाल।

खरीफ सीजन में श्रीअन्न फसलों की जमकर बुवाई किसानों ने की है, लेकिन बाजरा की खेती में किसानों कम रुचि दिखाई है। इसी वजह से बाजरा के रकबे में 1 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि, केंद्र सरकार ने 2024-25 में बाजरा की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 125 रुपये बढ़ा दिया है। कृषि एक्सपर्ट का मानना है कि बीते साल विपरीत मौसम और कीटो-रोगों के चलते फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे किसानों ने इस बार बुवाई क्षेत्र घटा दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसलों का बुवाई क्षेत्र 17 सितंबर 2024 तक 1096 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पहुंच गया है। इस वर्ष 410 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई, जो बीते साल की तुलना में 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक है। इसी तरह इस वर्ष 127.77 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई है, जो बीते साल से 9 लाख हेक्टेयर अधिक है। इसके अलावा इस वर्ष 193.32 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई है, जो बीते साल की तुलना में 3 लाख हेक्टेयर अधिक है। इसी तरह गन्ना की खेती 50 हजार हेक्टेयर से अधिक में की गई है।

किसानों ने मोटे अनाज फसलों की बंपर खेती की

श्रीअन्न फसलें यानी मोटे अनाज की खेती भी इस बार बंपर की गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष 189.67 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 183.11 लाख हेक्टेयर की गई थी। इस हिसाब से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार अधिक बुवाई की गई है। मोटे अनाज में सर्वाधिक बुवाई मक्का की गई है। बीते साल की तुलना में इस बार मक्का का बुवाई क्षेत्र 4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 87.50 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है।

1 लाख हेक्टेयर में कम हुई बाजरा की बुवाई

खरीफ सीजन में किसानों ने मक्का, रागी, ज्वार की जमकर बुवाई की है, लेकिन बाजरा की खेती से मुंह मोड़ लिया है। इसी वजह से बाजरा का बुवाई क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर घट गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 17 सितंबर 2024 तक देशभर में 69.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की खेती की गई है। जबकि, बीते साल समान अवधि तक 70.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की बुवाई की गई थी। इस हिसाब से इस बार किसानों ने करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की कम बुवाई की है।

इन वजहों से घटा बाजरा का रकबा

बाजरा किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर रखी है। केंद्र ने 2024-25 सीजन के लिए बाजरा का एमएसपी रेट 125 रुपये बढ़ाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। एमएसपी बढ़ने के बावजूद खेती का रकबा नहीं बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह फसल के लिए विपरीत मौसम और कीट, रोगों का प्रकोप भी है। जबकि, बड़ी संख्या में बाजरा किसान मक्का की ओर शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि, मक्का की सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके सरकार ने दिए हैं और एमएसपी रेट में 135 रुपये की बढ़ोत्तरी की है।

भंडारे वाला घी... दाल मे काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
कृषि विज्ञान केंद्र, भिंड (म.प्र.)

देसी घी को संस्कृत में घृत कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही घी का उत्पादन एवं उपयोग होता आया है। हमारे वेदों में भी गाय के घी का विस्तार से वर्णन मिलता है। घी न सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट और रुचिकर बनता है बल्कि भारत में घी का उपयोग औषधि और वैदिक पूजा पाठ में सदियों से किया जा रहा है। आज भी भारत में भारतीय गायों के घी की विशेष महत्व है। बद्री नस्ल की भारतीय गाय का घी सबसे महंगा बिकता है। देसी घी न सिर्फ हमारे शरीर को पुष्टि कारक बनाता है अपितु यह मस्तिष्क को क्रियाशील बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दुनियां का शीर्ष देसी घी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। भारत में वर्ष 2020 में 170 हजार मीट्रिक टन देसी घी का उत्पादन किया गया जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है जिसका घी उत्पादन भारत से लगभग आधा है।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि मंदिर के महाप्रसाद के लड्डुओं को बनाने में प्रयोग किये जा रहे गाय का घी मिलावटी पाया गया है। इस घी में पशुओं की चर्बी, फिश आयल आदि की मिलावट पाई गई है और यही घी मंदिर के प्रसाद के लिए बनाये जा रहे लड्डुओं में प्रयोग किया जा रहा था। इस खुलासे के बाद पूरे देश में सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ खिलवाड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। यह विषय पूरे देश में राजनीति का केंद्र बिंदु भी बन गया है। मिलावटी देसी घी की यह घटना दुनिया में प्रतिष्ठित आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी होने तथा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यह विषय उठाए जाने के कारण बहुत अधिक तूल पकड़ रही है।

लेकिन इस मिलावटी घी के संदर्भ में, में आपको देश के अन्य हिस्सों की ओर ले जाना चाहता हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आज पूरे देश मैं खासकर उत्तर भारत में भी मिलावटी देसी घी की प्रचुरता देखी जा सकती है। बात वर्ष 2018-19 की है मैं कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना में पदस्थ था। एक दिन क्षेत्र के एक गांव-अटा में हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे थे। इस गांव में किसान खेती-किसानी के साथ ही भैंस पालन भी बड़े पैमाने पर करते हैं। चर्चा में विषय निकल कर आया कि अधिकांश किसान अपनी भैंसों का दोनों समय अर्थात सुबह और शाम का दूध दूधिया अथवा गांव में बने दुग्ध संग्रह केंद्र पर वसा प्रतिशत के आधार पर बिक्री कर देते हैं।

इस चर्चा में मेरे द्वारा किसानों को समझाया गया कि वह अपनी भैंसों का सुबह का दूध जरूर बेचें, लेकिन शाम का दूध अपनी पुरातन ग्रामीण संस्कृति के अनुसार हाड़ी में गर्म करके मिट्टी के घड़ों (स्थानीय भाषा में कछरा) में जामन लगा दें। इस दूध से तैयार दही को सुबह मथकर चला लें। इससे किसानों को मक्खन और छाछ (मट्ठा) मिलेगा। छाछ व स्वयं प्रयोग कर सकते हैं जो दूध के बराबर ही फायदेमंद है। इससे उन्हें, उनके परिवार और पालतू पशुओं को पोषण सुरक्षा प्रदान होगी। साथ ही मक्खन से घी बनाकर वह बाजार में अच्छे भाव में बिक्री कर सकते हैं। इस पर एक किसान का कहना था कि इस समय बाजार में देसी घी के भाव 750 से लेकर 800 रुपए प्रति किलो हैं। जबकि बाजार में भंडारे वाला घी मात्र 120 किलो ही मिल रहा है। इसलिए कोई घी बनाने में इतनी मेहनत क्यों करेगा जब उसका घी कोई खरीदेगा ही नहीं ज्यादातर लोग भंडारे वाला घी ही प्रयोग करते हैं। इसलिए दूध बेचने में ज्यादा मुनाफा है।

ग्रामीणों ने बताया कि भंडारे वाले देसी घी को लोग आज पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान से लेकर किए जाने वाले भंडारे (प्रसादी) एवं दावतों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं भंडारे वाले घी की दावत करके लोग वाहवाही भी लूट रहे हैं कि फलां व्यक्ति ने देसी घी की दावत की है। यह भंडारे वाला घी स्थानीय बाजारों में शुद्ध देसी घी की तुलना में बहुत कम कीमत पर सर्व सुलभ है। बताया जाता है यह घी स्वाद, सुगंध और देखने में शुद्ध देसी घी जैसा ही लगता है। अब यहां चिंतन का विषय यह है कि जब गांव में दूध 50 लीटर बिक रहा है और सारा दूध जब बिक जाता है। इसके बाद यह भंडारे वाला देसी घी मात्र 120 किलो में आखिरकार आ कहां से रहा है?

अब चर्चा करते हैं देश के एक दूसरे राज्य और दूसरे शहर की मुझे सही तिथि तो याद नहीं है। लेकिन यह घटना वर्ष 2009 से 2012 के बीच की रही होगी। तत्कालीन समय यह खबर अखबारों की बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी। आगरा से फिरोजाबाद को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर छलेसर नाम की एक जगह पड़ती है। छलेसर के आसपास वन विभाग का कटीले बबूलों- झाड़ियों का एक बड़ा जंगल है। उस समय इस जंगल के बीचो-बीच प्रशासन द्वारा भट्टियों पर बड़ी-बड़ी कढ़ाईयों में दुधारू पशुओं की हड्डियों को उबालकर उनसे निकलने वाली चर्बी को एकत्र करने वाले माफिया को पकड़ा गया था। यह माफिया एक तथाकथित पार्टी का भाईचारे वाला माननीय था। यह घटना उन दिनों माननीय माफिया के सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण काफी चर्चा में भी रही रही थी। आखिर जो भी रहा हो हमें इससे कुछ ज्यादा लेना-देना नहीं है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि उस चर्बी (वसा) का आखिर क्या किया जा रहा था?

डेरी विशेषज्ञों की माने तो दूध से तैयार घी तथा पशु चर्बी खासकर डेरी पशु गाय-भैंस और हड्डियों से निकलने वाली फैट (वसा) दोनों ही एनिमल फैट होती है। इनके रासायनिक संगठन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मिलावट खोर इसी चीज का फायदा उठाकर डेरी पशुओं की हड्डियों को उबालकर निकाली गई वसा को परिष्कृत कर उसमें देसी घी का एसेंस मिलाकर बाजार में विभिन्न नाम से बिक्री के लिए उतार देते हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक तथा देश के कई हिस्सों में इस तरीके से हड्डियों से वसा एकत्र करने का काम अवैध तरीके से होता रहा है। अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों से भी पशु चर्बी एकत्र की जाती है। जिसका प्रयोग अखाद्य से लेकर खाद्य पदार्थों अर्थात घी बनाने तक में किये जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इस प्रकार से तैयार घी ही भंडारे वाला घी कहलाता है। वरना बाजार में इतना सस्ता घी किसी भी सूरत में मिलना संभव नहीं है। आज गांवों में भी भैंस का शुद्ध देसी घी ?1200 तथा भारतीय गाय का देसी घी ?1500 तक बिक्री किया जा रहा है। बहुत से लोग भारतीय देसी गाय के घी को ब्रांडिंग करके जैविक एवं ए-2 घी के नाम पर ?3500 प्रति किलो से अधिक तक की कीमत पर भी बिक्री कर रहे हैं। गांव में अधिकांश पशुपालकों द्वारा दूध बेचे जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध देसी घी मुश्किल से ही मिल पाता है। देश के बड़े और प्रतिष्ठित घी ब्रांडों द्वारा गाय और भैंस के दूध की क्रीम निकाल कर स्वचालित प्लांटों में घी तैयार किया जाता है। बाजार में ब्रांडेड कंपनियों का देसी घी आपको सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन बाजार में देसी घी के नाम पर जो सस्ता घी मिल रहा है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है? इसलिए अब भंडारे में देसी घी का प्रसाद पाने तथा चटकारे लेकर उंगलियां चाटते हुए दावत उड़ाने से पहले एक बार यह मंथन और चिंतन जरूर कर लेना कि कहीं आप देसी घी के नाम पर पशुओं की हड्डियों से निकाली हुई वसा अथवा पशु चर्बी से तैयार घी का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनने में जरूर खराब लगती है लेकिन आखिरकार है सोलह आने सच और एक सवाल यह भी छोड़ कर जाती है कि हमारा समाज पैसों के लिए और कितना नीचे तक गिरेगा।

विश्व रैबिज दिवसः रैबिज का टीकाकरण और जागरूकता ही है उपाय

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आकाश सुमन
» डॉ. शिवराज चौहान
» डॉ. रितेश वर्मा
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, महू, मप्र.

हर साल 28 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व रैबिज दिवस रैबिज के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि रैबिज एक गंभीर बीमारी है, जो न केवल पालतू जानवरों के लिए, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। रैबिज के मामलों में वृद्धि की वजह से इसे रोकने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

रैबिज एक वायरल संक्रमण है, जिसे रैबीड वायरस के कारण होता है। यह मुख्यतः कुत्तों, बिल्लियों, और अन्य वन्य जानवरों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति को काटता है, तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

लक्षण: रैबिज के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और संक्रमण के बाद के चरणों में गंभीर रूप लेते हैं:

प्रारंभिक लक्षण: बुखार, सिरदर्द, और सामान्य अस्वस्थता। ये लक्षण साधारण फ्लू के समान होते हैं।

गंभीर लक्षण: चिड़चिड़ापन, भ्रम, मांसपेशियों में ऐंठन, और अत्यधिक संवेदनशीलता। इसके बाद पागलपन और लकवा भी हो सकता है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है।

रैबिज का इतिहास: रैबिज का इतिहास कई सदियों पुराना है। प्राचीन समय में, इसे एक घातक बीमारी के रूप में देखा गया था। 19वीं सदी में, प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पैस्टर ने रैबिज के खिलाफपहला टीका विकसित किया। उनका यह कार्य रैबिज के खिलाफवैश्विक प्रयासों की शुरुआत का प्रतीक बना। इसके बाद, कई देशों में रैबिज के खिलाफटीकाकरण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिससे इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिली।

रैबिज के खिलाफ टीकाकरण का महत्व

टीकाकरण रैबिज के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। टीकाकरण से न केवल जानवरों की सुरक्षा होती है, बल्कि यह मनुष्यों के लिए भी सुरक्षा कवच का कार्य करता है।

टीकाकरण कार्यक्रम: पहला टीका: पालतू जानवरों को 12 से 16 सप्ताह की आयु में पहला टीका लगवाना चाहिए।

बूस्टर डोज: पहले टीके के एक वर्ष बाद बूस्टर डोज लगवाना आवश्यक है। इसके बाद, हर साल बूस्टर डोज का नियमित अनुसरण करना चाहिए, ताकि जानवरों को लगातार सुरक्षा मिलती रहे।

रैबिज से बचाव के उपाय: रैबिज से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

पालतू जानवरों का टीकाकरण: अपने पालतू जानवरों को नियमित रूप से टीका लगवाना न भूलें, क्योंकि यह उनकी और आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

संक्रमित जानवरों से दूरी: संक्रमित जानवरों से संपर्क करने से बचें, और यदि आपको किसी जानवर ने काटा है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

काटने की स्थिति में तुरंत चिकित्सा: यदि किसी जानवर ने काट लिया है, तो तुरंत डॉक्टर से संपकज करें। समय पर उपचार से रैबिज को रोका जा सकता है। कुत्ते बिल्ली के काटने पर तुरंत ही साबुन से घाव को बहते हुए पानी में धो लें। इसके बाद टीकाकरण सुनिश्चित करें।

रैबिज से संबंधित मिथक और तथ्य: रैबिज के बारे में कई मिथक भी प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, यह धारणा है कि रैबिज केवल कुत्तों के काटने से ही फैलता है, जबकि यह अन्य जानवरों से भी फैल सकता है। सही जानकारी का प्रसार जरूरी है, ताकि लोग सही कदम उठा सकें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, साल 2024 के विश्व रेबीज दिवस की थीम ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज या 'रेबीज की सीमाओं को तोड़ना' है, जो घातक बीमारी के खिलाफमुकाबले में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों को सामने लाता है। विश्व रैबिज दिवस हमें यह याद दिलाता है कि रैबिज एक नियंत्रित बीमारी है, यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें। टीकाकरण, जागरूकता, और समुदाय के सहयोग से, हम रैबिज के प्रसार को रोक सकते हैं और मानव तथा जानवरों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

आइए हम सभी मिलकर रैबिज के खिलाफलड़ाई में कदम बढ़ाएं और अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित रखें। इससे न केवल हम अपने जानवरों की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि अपनी और अपने परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।

...तो नहीं बचेगी खेती के लायक जमीन लकड़ी का भी हो जाएगा अभाव

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण फसल और पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त भूमि कम हो जाएगी, जिससे इन दो अहम संसाधनों के उत्पादन में सीधी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन उन इलाकों को बदल रहा है जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त हैं। इसी बीच, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक गंभीर समस्या का पता लगाया है, उन्होंने पाया कि जैसे-जैसे फसलों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग बदला जाजा रहा है, वैसे-वैसे पेड़ उगाने के लिए जरूरी जमीन कम हो रही है। ये पेड़ जिनसे लकड़ी हासिल की जाती है, इनका हमारे जीवन में अहम भूमिका है। कागज, कार्डबोर्ड से लेकर फर्नीचर और इमारतों तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लकड़ी के उत्पादन और फसलों के उत्पादन के लिए भूमि के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को अब तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन यह एक उभरता हुआ मुद्दा बनने जा रहा है क्योंकि दोनों के लिए हमारी मांग लगातार बढ़ रही है।

अध्ययन में पाया गया कि मौजूदा वन भूमि का एक चौथाई से अधिक, लगभग 32 करोड़ हेक्टेयर, जो भारत के आकार के बराबर है, सदी के अंत तक खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। लकड़ी प्रदान करने वाले अधिकतर पेड़ वर्तमान में उत्तरी गोलार्धमें अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस में स्थित हैं। अध्ययन में पाया गया कि 2100 तक मौजूदा जंगल वाली भूमि का 90 फीसदी हिस्से पर खेती की जाएगी और ये भूमि इन चार देशों में होगी। विशेष कर रूस में लकड़ी का उत्पादन करने वाली दसियों लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयोग की जाएगी, जो कि अमेरिका, कनाडा और चीन की कुल भूमि से भी अधिक है। यहां आलू, सोया और गेहूं की खेती की जाएगी।

शोध में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण साल 2050 तक दुनिया भर में भोजन की मांग दोगुनी हो जाएगी। दुनिया भर में लकड़ी की मांग भी उसी समय सीमा में दोगुनी होने का अनुमान है। क्योंकि लकड़ी निर्माण के लिए कंक्रीट और स्टील का कम कार्बन वाला विकल्प है।

लकड़ी के उत्पादन को बोरियल या उष्णकटिबंधीय जंगलों में स्थानांतरित करना सही विकल्प नहीं है, क्योंकि उन इलाकों में पेड़ हजारों सालों से अछूते हैं और उन्हें काटने से भारी मात्रा में कार्बन निकलेगी जिससे जैव विविधता को खतरा होगा।

कई गांवों में पानी में डूबी है फसल, दाने में पड़ेंगे काले धब्बे।

भारी बारिश से चंबल में हजारों हेक्टेयर में लगी बाजरा की फसल पर संकट

जागत गांव हमार, मुरैना ।

सितंबर महीना बाजरा की फसल के पकने का समय है और इस समय लगातार हो रही बारिश ने किसानों को संकट में ला दिया है। कई गांवों में बाजरा के खेत जलमग्न हैं। फसल गल रही है। ऐसे में यदि गुणवत्ता प्रभावित रही तो जो अनाज समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाएगा। इससे पहले के तीन सालों में भी चंबल के किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य पर नहीं बिक सका था। चंबल के मुरैना और भिंड जिले में प्रदेश का 85 फीसद से ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है।

मुरैना में दो लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती- मुरैना में दो लाख और भिंड में 70 हजार हेक्टेयर में बाजरा की खेती हो रही है। इस समय फसल में बालियां आ गईं है, दाने बन रहे हैं। दूसरी तरफ अतिवर्षा से हालत यह है, कि बाजरा के खेतों में चार से छह फीट तक पानी भर गया है। लगातार बारिश व जलभराव ने बालियों के फूल झड़ गए हैं, दाने छोटे रह जाएंगे और काले रंग के धब्बे पड़ने की आशंका है। समर्थन मूल्य पर वही अनाज खरीदा जाता है, जो फाइन एवरेज क्वालिटी (एफएक्यू) जांच में पास हो। छोटे आकार व काले धब्बों के कारण बीते तीन साल से समर्थन मूल्य के लिए चंबल का बाजरा फेल हो रहा है। इस साल बारिश व बाढ़ ज्यादा है, इसीलिए किसान चिंतित हैं।

धान भी नहीं झेल पा रही पानी की मार

धान की खेती पानी के बीच होती है, लेकिन लगातार हो रही भी धान पर दुष्प्रभाव डाल रही है। खेतों में इतना पानी भर गया है, कि धान के पौधे पानी के अंदर दो-दो फीट गहरे डूबे हुए हैं। जहां धान के पौधे लहलहा रहे थे, वहां जलभराव से तालाब जैसा नजारा है। मुरैना में 6000, भिंड में 75000 और श्योपुर में 40000 हेक्टेयर में धान की फसल हो रही है।

बाजरा का दाना कमजोर होगा

बारिश से बाजरा के पौधे गिरे हैं। जहां पानी भरा है उन खेतों के पौधे गल भी रहे हैं। बारिश से बालियों के फूल झड़ने से पैदावार पर असर पड़ेगा। दाना कमजोर होगा, उसकी चमक फीकी रहेगी। ऐसा अनाज समर्थन मूल्य के एफएक्यू मानकों पर पास नहीं होता और किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य पर बिकना मुश्किल हो जाएगा।

- डॉ. संदीप सिंह तोमर, कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा इन्दौर का महिला मैकेनिक गैरेज

जागत गांव हमार, भोपाल

महिला मैकेनिक गैरेज, नाम सुनकर अलग सा अहसास होता है लेकिन संभवत: प्रदेश का यह पहला महिला मैकेनिक गैरेज है जो कि इंदौर में है। इस गैरेज के माध्यम से करीब 100 से अधिक महिलाएं, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है। स्वच्छता में नंबर वन रहने वाला इंदौर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनकर उभर रहा है। महिला गैरेज में सारा काम महिलाएं ही कर रही हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए भारत को गढ़ रही हैं। घर के कामकाज को निपटाकर यहां काम करने आने वाली महिलाएं समय से अपने दायित्व को बेहतर तरीके से पूरा कर रही हैं।

महिला मैकेनिक सुश्री शिवानी रघुवंशी, श्रीमती दुर्गा मीणा एवं श्रीमती मेघा खराटे ने बताया काम के शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई लेकिन किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के जीवन साथी ने उत्साह को कम नहीं होने दिया और लगातार प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया जब नए थे तो काम में थोड़ी झिझक होती थी लेकिन हौसले और आत्मविश्वास से आज गैरेज के संचालन से हमें एक नई पहचान मिल रही है। हमें आगे बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिला है। यहां काम करने वाली महिला मैकेनिकों को 9 से 15 हजार रूपये तक की सैलरी मिलती है। इस काम ने इन महिलाओं को एक अलग पहचान दिलाई है। आसपास के क्षेत्र में दुपहिया वाहन का परिचालन करने वाली महिलाएं इसी गैरेज पर अपने वाहनों का सुधार कार्य करवाती है।

20 से 25 महिलाएं कार्य कर रहीं

संस्था के डायरेक्टर राजेन्द्र बंधु बताते हैं कि संस्था के माध्यम से पिपल्याहाना, हवा बंगला और पालदा में महिला गैरेज संचालित किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 20 से 25 महिलाएं नियमित रूप से कार्य कर रही है तथा संस्था की ओर से करीब यहां काम सीखने के बाद 100 से अधिक महिलाओं को प्रतिष्ठित दो पहिया वाहन कंपनियों के सर्विस सेन्टरों में प्लेसमेंट कराया गया। फर्म और सोसायटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध संस्था के माध्यम से इस महिला गैरेज की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया हमारी सोच है कि महिलाएं स्वयं कंपनी का संचालन करते हुए अन्य वाहन कंपनियों की डीलरशिप लेकर काम करें। महिला मैकेनिक गैरेज के माध्यम से समाज में यह संदेश देने का प्रयास है कि जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। महिलाएं पुरूषों के समान हर काम कर सकती है। बस आवश्यकता है उन्हें मार्गदर्शन और अवसर देने की। आज महिलाएं मैकेनिक है कल पूरी कंपनी का संचालन करेंगी। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी तथा रोजगार के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

-पशुओं की गणना के लिए टैबलेट का वितरण

50 हजार पशुओं में मोबाइल यूनिट

गोबर से बनाए पेंट को मान्यता देने का सुझाव

जागत गांव हमार, भोपाल।

भुवनेश्वर में आयोजित देश के सभी राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों की बैठक में पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने गोबर से बनाए गए पेंट को मान्यता देकर उसके विपणन का सुझाव दिया। कहा कि इससे गौशालाएं आय अर्जित कर सकेंगी। यह भी कहा कि पशुओं के उपचार के लिए 50 हजार पशुओं पर एक मोबाइल यूनिट होनी चाहिए और पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों बेहतर बनाया जाए। इस माह से प्रारंभ होने वाली 21वीं पशु संगणना के लिए कर्मचारियों को टैबलेट भी प्रदान करने का सुझाव दिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित सेंट्रल सीमन स्टेशन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। संस्था की ओर से ट्राफी एवं प्रमाण पत्र प्रबंध संचालक डा. राजू रावत एवं प्रभारी डाक्टर दीपाली देशपांडे ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा पूरा

सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय ने कहा के डेयरी सेक्टर असंगठित है, इसे सहकारी समितियां के माध्यम से विकसित करें। इस संबंध में राज्यों को जागृत होना होगा तथा गंभीरता से सोचना होगा, जिससे दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

मुख्य सचिव वीरा राणा ने उपार्जन की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा

प्रदेश में 25 अक्टूबर से दिसंबर तक होगी सोयाबीन की खरीदी, ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन होगा

जागत गांव हमार, भोपाल।

मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। इसके लिए पंजीयन 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा। मुख्य सचिव वीरा राणा ने उपार्जन की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन की बेहतर व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग को गिरदावरी कराए। भंडारण राज्य भंडार गृह निगम करेगा और बारदाना की व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि गुणवत्तायुक्त सोयाबीन खरीदी में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर परेशानी न आए,यह सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदा जाएगा। भारत सरकार की एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन होगा। खरीदी 90 दिन की जाएगी। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई है। सर्वाधिक क्षेत्र मालवांचल में है।

उपार्जन लक्ष्य निर्धारित होना बाकी

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित होना बाकी है। कुछ स्थानों पर नाफेड उपार्जन करेगा और बाकी स्थानों पर मार्कफेड द्वारा विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत खरीदी की जाएगी। सहकारी समितियों को उपार्जन केंद्र बनाया जाएगा और भंडारण की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। भारत सरकार सोयाबीन को सेंट्रल पूल में लेकर बाहर नहीं भेजती है, तब तक भंडारण में होने वाली प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी और भुगतान तीन दिन के भीतर सीधे खाते में होगा।

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण संपन्न

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने कौशल विकास पर दिया जोर

जागत गांव हमार, ग्वालियर।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर द्वारा पांच दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह के मार्गदर्शन में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रीता मिश्रा द्वारा ब्लॉक घाटीगांव के ग्राम बरई में सम्पन्न किया गया। इस प्रशिक्षण में 46 युवा महिलाओं ने सफलतापूर्वक भागीदारी की। सरकार की ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य के साथ कौशल विकास हेतु इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिससे प्रशिक्षण उपरांत युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। कृषि के विभिन्न उत्पाद जैसे फल, सब्जियां इत्यादि जल्द ही खराब हो जाते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता भी बहुत कम होती है। अत: मौसमी फल, सब्जियां, विभिन्न खाद्यान इत्यादि को प्रसंस्करण द्वारा लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है तथा मूल्यवर्धित उत्पादों द्वारा आयज अजज्न भी किया जा सकता है। युवा महिलाओं ने प्रशिक्षण में वैज्ञानिक विधि द्वारा लघु स्तर पर विभिन्न प्रकार के अचार, मुरख्या, चिप्स, पापड इत्यादि का निमार्ण करने की कला सीखी। युवाओं ने स्थाई रूप से उपलब्ध सहजन जैसे लाभकारी पेड़ की पत्तियों से पाउडर बनाना तथा सहजन की फलियों का अचार बनाने का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रसंस्करण की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थियों ने आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के मिश्रण से बहुमिश्रित आटा, बहुमिश्रित दलिया, पोष्टिक लड्डू बनाने सीखे। उन्होंने दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पाद जैसे: पनीर, मिठाई, घी आदि बनाने भी सीखे। तैयार प्रसंस्कृत एवं मूल्यवर्धित उत्पादों की पैकिंग की विभिन्न विधियां भी प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाई गई। डॉ. निश्रा ने युवाओं को तैयार मूल्यवर्धित उत्पादों को स्वयंसहायता समूह के माध्यम से विपणन करने की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण को सफल बनाने में केन्द्र के अन्य वैज्ञानिकों डॉ. रश्मि वाजपेई, डॉ. जितेन्द्र सिंह राजपूत एवं डॉ. अमिता शर्मा ने उपरोक्त विषय से संबंधित तकनीकी व्याख्यान दिये। इस प्रकार आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण में युवाओं ने प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की विभिन्न विधाओं को विस्तार से जाना।

समन्वित कीटनाशी प्रबंधन से उत्पादन में वृद्धि संभव

जागत गांव हमार, बड़वानी।

कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस.के. बड़ोदिया के मार्गदर्शन में कृषि आदान विक्रेताओं हेतु आयोजित डिप्लोमा कार्यक्रम में गत दिनों कीट रोग विशेषज्ञ डॉ. जी.एस. कुलमी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र खरगोन ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर डॉ. एस.के. बड़ोदिया ने स्वागत करते हुए जानकारी दी की डॉ. कुलमी जी विगत कई वर्षों से फसलों में कीट- व्याधि की रोकथाम के क्षेत्र कार्य कर रहे हैं व इन्हें समन्वित कीटनाशी प्रबधंन का प्रायोगिक अनुभव प्राप्त है, इनके द्वारा कई अनुसधान कार्य किये गये। डॉ. कुलमी ने निमाड़ क्षेत्र में फसलों पर लगने वाले प्रमुख कीटों व उनके जीवनचक्र की जानकारी देकर रोकथाम के उपाय बतायें। साथ ही फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन हेतु अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, बीजोपचार कर बुवाई करने से व बीजोचार हेतु जैव उर्वरकों राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा विरडी का प्रयोग एवं नाशीजीव प्रबंधन हेतु प्रक्षेत्र पर 8-10 फेरोमेन ट्रेप प्रति एकड़ के प्रयोग की बात कही। जिससे कीट-व्याधि के प्रकोप से फसल सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त सब्जियों में लगने वाले कीटों में प्रमुख रूप से फ्रूट बोरर से बचाव के उपाय की जानकारी दी ।

द्वितीय सत्र में डॉ. कुलमी ने खरपतवारों की पहचान एवं विभिन्न फसलों में उपयोग किये जाने वाले शाकनाशी की मात्रा की गणना की विस्तृत जानकारी दी तथा जैविक एवं रासायनिक दवाओं के अनुशंसित मात्रा के प्रयोग एवं कृषि के मित्र कीटों के संरक्षण हेतु भी जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर बी.एम. कृषि महाविद्यालय खंडवा की रेडी कार्यक्रम की छात्राओं सहित केन्द्र के वैज्ञानिक एवं अधिकारी डॉ. बी कुमरावत व यू.एस. अवास्या उपस्थित रहे ।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बी.एस किरार, केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आर.के. प्रजापति, डॉ. एस.के. जाटव, डॉ. आई.डी. सिंह, जयपाल छिगारहा आदि द्वारा ग्राम गणेशगंज में स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत स्वाभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कृषकों को अपने-अपने घरों के आसपास बनी नालियाँ की, गाँव में लगे हैंडपंपों के आसपास की सफाई करना बहुत जरूरी है। यदि गंदा पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियाँ जैसे - डेंगू, मलेरिया और अनेकों रोग पैदा होते हैं इसलिए साफ-सफाई बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार किसान भाईयों को बताया गया कि खेतों में खरपतवार हो जाते हैं जिससे फसल को बहुत हानी होती है इसलिए अपने खेतों में अनचाहे पौधों को निकाल देना चाहिए जिससे हमारी फसल की उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि प्रत्येक परिवार अपने-अपने घरों के सामने की नालियाँ एवं सड़क की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो हमारे गाँव में बीमारियाँ फैलने की संभावना भी कम हो जाती है इसलिए गाँव में जगह-जगह कचरे एवं गोबर के ढेर न बनायें, एक निश्चित स्थान पर ही कचरा को इक्ठा करके कम्पोस्ट खाद बनायें।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने उपार्जन के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जागत गांव हमार, मंडला।

जिला उपार्जन समिति की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि एक दिसंबर से शुरू होने वाले उपार्जन के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। उपार्जन का गहन पर्यवेक्षण करें तथा गुणवत्तापूर्ण फसल ही खरीदें। उपार्जन से पूर्व नाप तौल कांटा का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उपार्जन के पश्चात आगामी एक सप्ताह में किसानों को भुगतान करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों के पंजीयन और सत्यापन की स्थिति को बेहतर बनाएं। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकान निर्धारित समयावधि में खोलते हुए शत प्रतिशत हितग्राहियों को गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों को चिन्हित करते हुए उनका पंजीयन करें, जिससे वहां पर मजदूर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना, पीडीएस, एमडीएम, भंडारण, धान मिलिंग की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में लगी बुरहानपुर के केले से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी

बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले में 'एक जिला-एक उत्पाद' के अंतर्गत केला फसल का चयन किया गया है। जिले में केला फसल के प्रसंस्करण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे केला चिप्स, केला पाउडबनानार, स्टीक, मिठाईयाँ आदि तैयार किये जा रहे हैं, साथ ही केला फसल के तने के रेशे से विभिन्न तरह के हैण्डी क्राप्ट, डोरमेट, योगामेट, टोपी, झाड़ू, टोकनी, घड़ी इत्यादि वस्तुएं बनायी जा रही है। उपसंचालक उद्यानिकी राजू बड़वाया ने जानकारी देते हुए बताया कि, जिले के ग्राम बोहरडा निवासी युवा उद्यमी शुभम पाटिल एवं उनकी टीम द्वारा कृषक संगम एग्री प्रोसेसिंग फार्मर प्रोडयूसर कंपनी लि. का गठन कर केले से निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग हेतु पहल की जा रही है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में केला प्रसंस्करण से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई । उपसंचालक ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि, केले के प्रसंस्करण से निर्मित उत्पादों को देश-विदेश में पहचान मिल रही है। जिससे जिले में केला फसल से निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ेगी। मार्केटिंग बढ़ने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

कार्यक्रम की शुरूआत अतिथियों द्वारा 'एक वृक्ष मां के नाम' अंतर्गत पौध रोपण एवं मां सरस्वती की पूजा के साथ की गई

राष्ट्रीय पोषण माह में अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन

जागत गांव हमार, बैतूल।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार, बैतूल में महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अनिमेष चटर्जी, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम् रहे तथा विषिष्ट अतिथि के रूप में गौतम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बैतूल उपस्थित रहें। इनके अतिरिक्त कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा के डॉ. विजय अग्रवाल, वैज्ञानिक, डॉ. सीमा द्विवेदी, ग्रंथपाल तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल के समस्त वैज्ञानिक, बैतूल ग्रामीण विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, मषरूम उत्पादन प्रषिक्षण के प्रषिक्षणार्थी तथा रावे की छात्राएं उपस्थित थीं।

कार्यक्रम की शुरूआत अतिथियों द्वारा 'एक वृक्ष मां के नाम' अंतर्गत पौध रोपण एवं मां सरस्वती की पूजा के साथ की गई। केन्द्र प्रमुख डॉ. व्ही.के. वर्मा द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अन्न डलिया देकर किया गया जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, किनोवा आदि अन्न शामिल थे।

कुपोषण दूर करने पर जोर

डॉ. वर्मा ने अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय पोषण माह एवं अन्न के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी तथा कुपोषण को दूर करने हेतु अन्न को अपनी थाली में शामिल करने के लिए आग्रह किया। गौतम अधिकारी द्वारा अपने भाषण में पोषण माह का महत्व एवं जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा जिले में चल रहे पोषण वाटिका हेतु केन्द्र द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर आभार व्यक्त किया।

आहार में अन्न के उपयोग पर डाला प्रकाश

केन्द्र के खाद्य वैज्ञानिक डॉ. एम.पी. इंगले द्वारा पोषण आहार में अन्न के उपयोग पर प्रकाष डालते हुए अन्न में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डॉ. इंगले ने कहा कि अन्न का मानवीय शरीर में विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह नियंत्रण, पाचन तंत्र सुधार, खनिज तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियां आदि को दूर करने हेतु उपयोग करना फायदेमंद है।

अन्न व्यंजन प्रतियोगियों को दिया गया प्रमाण पत्र

अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. चटर्जी द्वारा केन्द्र की गतिविधियों की सराहना की एवं भारत सरकार के कौशल विकास क्कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्र पर प्रषिक्षण प्राप्त मशरूम उत्पादक कृषकों को प्रमाण पत्र तथा अन्न व्यंजन प्रतियोगिता में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रषस्ति पत्र प्रदान दिए गए। तत्पश्चात पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम के अंतगज्त आयोजित पोषण आहार प्रदर्षनी का अवलोकन माननीय अतिथियों द्वारा किया गया। इसके साथ ही कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा की रावे छात्राओं द्वारा अन्न के महत्व को रेखांकित करते हुए एक नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतीकरण माननीय अतिथियों के समक्ष किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजीव वर्मा द्वारा आभार प्रदर्षन किया गया। उक्त कार्यक्रम में आर.डी. बारपेटे, डॉ. मेघा दुबे, डॉ. संजय जैन, नेपाल बारस्कर, सौरभ मकवाना आदि का विषेष योगदान रहा।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा स्वछता कार्यक्रम का आयोजन

शहडोल। कृषि विज्ञान केन्द्र शहडोल द्वारा स्वछता ही सेवा के स्वभाव स्वछता – संस्कार स्वछता के तहत केन्द्र के वैज्ञानिक दीपक चैहान द्वारा ग्राम बन्डीकला में स्वक्षता कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को बता की स्वच्छता मानव के चरित्र की सुंदरता के दृष्टिकोण के साथ ही स्वस्थ एवं बीमारियों से मुक्त समाज के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं से शुरुआत करते हुए अपने घर परिवार, गली मोहल्ले, गांव, शहर, नगर, कस्बा के आसपास में ना तो गंदगी करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे के लिए प्रेरित किया। बेहतर स्वच्छता लिए महिलाओं को उचित स्तर पर ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबंधन की आवश्यकताओं और अन्य विभिन्न पहलुओं का समायोजन जरूरी है।

वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई

रीवा। कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता डॉ एसके त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा म प्र में कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए केंद्र के प्रमुख डॉ ए के पांडेय ने कहा कि अपने आसपास साफ सफाई रखने जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है और संक्रामक बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। कार्यक्रम के नोडल एवं पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉ अखिलेश कुमार ने बताया कि स्वच्छता से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे का उपयोग खाद बनाने में होता है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसलों का उत्पादन बढ़ता है। इस अवसर पर केंद्र के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया द्य

प्रक्षेत्र प्रदर्शन भ्रमण कर दी किसानों को जानकारी

जागत गांव हमार, रीवा।

कृषि मंत्रालय भोपाल नें कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, भारत सरकार के तहत उड़द, अरहर, सोयाबीन पर कृषक प्रक्षेत्रों में आयोजित किये गये प्रक्षेत्र प्रदर्शनों का अवलोकन किया। कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता डा एसके त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. अजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में केन्द्र द्वारा उड़द , अरहर, सोयाबीन का जिले

के विभिन्न ग्रामों में प्रदर्शन आयोजित किये गये कार्यक्रम प्रभारी डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी एवं डॉ. स्मिता सिंह नें भोपाल से आए अधिकारी को दलहन विकास के वारे में विस्तृत जानकारी दिये, कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा के वैज्ञानिक का दल जिसमें डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी, डॉ. स्मिता सिंह, एवं डॉ. केवल सिंह बघेल के साथ ग्राम खजुहाकला, माहसाव, चौडीयार, जोकिआ एवं रीठी में आयोजित किये गये प्रदर्शनों का भ्रमण किया। इस अवसर पर प्रगतिशील कृषक परमसुख चौरसिया, अशोक पटेल, रजनीश तिवारी, राजाराम पटेल, राजेश पटेल उपस्थित रहे।

दलहन विकास निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दलहन एवं तिलहन फसल का अवलोकन किया

जागत गांव हमार, टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दलहन 100 हेक्टेयर, तिलहन 40 हेक्टेयर उसके अतिरिक्त तिलहन मॉडल ग्राम (ओ.एम.वी.) विशेष परियोजना अंतर्गत फसल मूंगफली 40 हेक्टेयर एवं तिल 60 हेक्टेयर खरीफ 2024 में प्रदशज्न लगाया गया था । विगत दिवस दलहन विकास निदेशालय (भारत सरकार) भोपाल से सरजू पल्लेवार (एस.आई.) के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चयनित ग्रामों- मनगावं, जनकपुर, महोबिया, बीघा, कोडिया एवं नादिया दलहन(उड़द), तिलहन (मूंगफली एवं तिल) का निरीक्षण किया । अग्रिम पंक्ति प्रदशज्न के नोडल अधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, वैज्ञानिक डॉ. सतेन्द्र कुमार ने प्रदशज्न का भ्रमण एवं परीक्षण के दौरान किसानों से प्रजाति, दवा एवं जैव उर्वरक जो किसानों को दिया गया था उनकी विस्तृत जानकारी एवं

विशेषताओं के बारे में सरजू पल्लेवार द्वारा किसानों से जानकारी ली गई । मूंगफली, तिल एवं उड़द की प्रजाति से कृषक पूर्णरूप से संतुष्ट हैं । कृषक भ्रमण के दौरान कृषको को एन.पी.एस.एस. एप के बारे में बताया गया । जिससे किसान भाई घर बैठे एप के माध्यम से फसल में लगने वाले रोग, कीट व्याधि की पहचान कर एवं सम्बंधित उचित दवा का प्रयोग कर फसल को रोगों एवं कीटों से प्रभावित होने से बचा सकते है । अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दलहन के नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. प्रजापति, डॉ. एस.के. जाटव एवं जयपाल छिगारहा वाय.पी.-2, द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दलहन फसल उड़द का निरीक्षण भी सरजू पल्लेवार द्वारा ग्राम कोडिया, बीघा एवं नादिया ग्राम में कराया गया उपरोक्त ग्राम के हितग्राहियों को भी एन.पी.एस.एस. एप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ।

मप्र सरकार ने हरदा और देवास जिले के लिए बनाया था ब्रांड एंबेसडर

किसानों के साथ धोखा, बांस लगवाकर गायब हुई आर्टिसन एग्रोटेक, खरीदने का किया था एग्रीमेंट

दो जिलों के किसानों के लिए बांस मिशन बन गया एक सिरदर्द

जागत गांव हमार, देवास।

मध्य प्रदेश में एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत दो जिलों के किसानों के लिए बांस मिशन एक भारी सिरदर्द बन गया है। आर्टिज़्सन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने किसानों को बांस लगाने और खरीदने का आश्वासन देकर एग्रीमेंट किए थे। लेकिन अब कंपनी के कर्ताधर्तापिछले छह महीनों से गायब हैं, जिससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

मप्र सरकार ने बनाया था ब्रांड एंबेसडर

कंपनी को 2019 में मप्र सरकार द्वारा देवास और हरदा जिलों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था। आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों को बांस लगाने के लिए एग्रीमेंट किया, जिसमें 40 साल तक या बांस की आयु पूरी होने तक कंपनी को प्रति मीट्रिक टन 2550 रुपए पर बांस खरीदने का वादा किया गया था। किसानों ने कंपनी पर विश्वास किया और बांस की खेती में भारी निवेश किया, लेकिन अब जब फसल तैयार हो गई है, तो कंपनी के अधिकारी लापता हो गए हैं।

किसानों का साथ नहीं दे रहा वन विभाग

इस पूरे मामले में सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के अफ्सर अब भी कंपनी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि किसानों की हालत दयनीय है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी घाटे में है, इसीलिए वह बाजार से गायब है। यह स्थिति तब है जब सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को बांस उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया और कंपनी को सरकारी बैठकों में विशेष स्थान दिया गया।

किसानों की मुसीबतें बढ़ीं

किसानों का कहना है कि उन्होंने वन विभाग और कंपनी पर भरोसा कर अपनी जमीन पर बांस लगाए थे, लेकिन अब उनके लिए यह फसल बोझ बन गई है। आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लापता होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बल्कि उनकी मेहनत भी बेकार हो गई है। सरकार की योजनाओं और निजी कंपनियों के साथ किए गए एग्रीमेंट के प्रति अब किसानों का भरोसा डगमगाने लगा है।

सरकारी योजना पर सवाल

इस घटना ने एक जिला, एक उत्पाद जैसी सरकारी योजनाओं की पारदर्शिज़्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्टिसन एग्रोटेक जैसी कंपनियों को बिना सही जांच-पड़ताल के ब्रांड एंबेसडर बनाना और सरकारी बैठकों में शामिल करना, सरकार की नीतियों की विफ्लता को दर्शाता है। अगर जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कारज़्वाई नहीं की गई, तो भविष्य में अन्य योजनाओं के प्रति किसानों का विश्वास और भी कम हो सकता है। सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रज़्वाई करें। साथ ही, किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

नौ रेंज में 60 विशेषज्ञों के साथ 20 कैम्प में एप में कैद किया जा रहा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ 3 दिनी तितलियों का सर्वे, 22 को आएगी रिपोर्ट

जागत गांव हमार, भोपाल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन दिवसीय तितली सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। नौ रेंज में 60 वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ वनकर्मी 20 कैम्प में तितली की विभिन्न प्रजातियों को एप में कैद किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी व तितलियों की प्रजाति ज्ञात करना है। टाईगर रिजर्व प्रबंधन अनुसार बांधवगढ़ के सभी 9 रेंज (कोर व बफर रेंज) में यह सर्वेक्षण का काम चलेगा। जानकारी अनुसार 1536 वर्ग कि.मी. में फैले बांधवगढ़ के भीतर करीब 70 तितलियों की प्रजाति पाई जाती हैं। खासबात यह है कि टीम में शामिल नेचर्लिस्ट, बीटगार्ड व श्रमिकों के साथ कैम्प में रहेंगे। जंगल के भीतर दलदली व जल स्त्रोतों के समीप पहले से ही तितली के अनुकूल एरिया को चिन्हित कर लिया गया था। शुक्रवार की सुबह कैम्पों से सर्वे टीम जंगल के लिए रवाना हुई। मौके पर ही मिली तितली प्रजाति को एप में स्टोर किया गया। सर्वेक्षण के आखिरी दिन 22 सितंबर को सर्वे की रिपोर्ट फाइनल की जायेगी। उप संचालक पीके वर्मा ने बताया शुक्रवार की सुबह सर्वे टीम को पेट्रोलिंग कैम्प के लिए रवाना किया गया है। एक कैम्प में तीन वन्यजीव विशेषज्ञ रहेंगे। एक कैम्प में तीन विशेषज्ञों के अलावा बीटगार्ड व दो सुरक्षा श्रमिक को रखा गया है। साथ ही वाइल्ड लाइफ संस्था की मदद ली गई है। ये सर्वे टीम जंगल में ही वन श्रमिकों के साथ रहेगी। सुबह से पैदल चलकर तितलियां के रहवास वाली जगह में पहुंचेगी।

इसके पूर्व यहां अनुमानित 70 से अधिक प्रजातियां पाई जाती थीं

बांधवगढ़ में पहली बार तितलियों का सर्वेक्षण हो रहा है। इसके पूर्व यहां अनुमानित 70 से अधिक प्रजातियां पाई जाती थीं। इस सर्वे के बाद बांधवगढ़ में बाघ, हाथी जैसे विशालकाय जीव के अलावा यहां की जैवविविधता की खासियत को सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वन व वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता का उद्देश्य भी है। एक बार मैपिंग हो जाने के बाद यह उपलब्धि भी जैवविविधता में जुड़ जाएगी। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया श्री गौरव चौधरी ने बताया कि अलग-अलग कैम्प में डब्ल्यूएनसी की टीमें हैं। वे कैम्प एरिया में जाकर देखेंगी, किस क्षेत्र में तितली की कौन सी प्रजाति है। सर्वे के बाद तितली की बायोडायवर्सिटी क्या है, इसका एक रिकार्ड भी बनाया जाएगा। सर्वे का कार्य ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।

नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम शुरू

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 100 दिनों में किसानों के हित में कृषि विकास की 6 सूत्रीय रणनीति, निर्णयों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है, जिसमें किसानों द्वारा सीधे खेत

से फसल के रोग / कीट की फोटो भेजने पर वैज्ञानिकों द्वारा तुरंत सलाह दी जाएगी।

किसानों को मिलेगी तत्काल सहायता: कृषि मंत्री ने बताया कि फोटो भेजते ही किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा उचित सलाह दी जाएगी, जिससे तत्काल बीमारी पर रोक संभव होगी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)